पत्रकारिता के आचरण के मानकों का पालन जरूरी-राजेंद्र पुरोहित

तेवर वही, अंदाज नया .....!
साप्ताहिक

उज्जैन टाइम्स

डाक रजिस्ट्रेशन नं. मालवा डिवीजन-
L2/65/RNP/397/2024-2026

प्रधान सम्पादक : मनमोहन शर्मा

RNI No. 7583/61

● वर्ष : 63, अंक : 24 ● उज्जैन, मंगलवार दिनांक 12-03-2024 से 18-03-2024 तक ● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 2 रुपये

नया प्रेस एक्ट पत्रकार एवं पत्रकारिता की बेहतरी के लिये होगा मददगार, जनसम्पर्क विभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

इंदौर। पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को जीवित रखने के लिये पत्रकारिता के आचरण के मानकों का पालन जरूरी है। पत्रकारिता के आचरण के मानकों का पालन कर समाज में विश्वसनीयता कायम रखी जा सकती है। नया प्रेस एक्ट पत्रकार एवं पत्रकारिता की बेहतरी के लिए मददगार होगा। नये प्रेस एक्ट से पत्रकारिता के आचरण के मानकों का पालन कर समाज में हम सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। नये प्रेस एक्ट से कार्यक्षमता में वृद्धि भी होगी तथा कार्य आसान और सुविधाजनक होगा।

उक्त उदगार अतिथियों द्वारा संभागीय जनसंपर्क कार्यालय इंदौर द्वारा प्रेस एक्ट और पत्रकारिता के आचरण के मानक विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में व्यक्त किए गए। इस कार्यशाला में वरिष्ठ पत्रकार श्री रघुवीर तिवारी भोपाल, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी, स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री प्रवीण खारीवाल और वरिष्ठ पत्रकार श्री नवनीत शुक्ला ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने उक्त विचार व्यक्त किये।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री अरविंद तिवारी ने कहा कि पुराने प्रेस एक्ट में विसंगतियां थी। नये प्रेस एक्ट में इन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। नया प्रेस एक्ट कार्य क्षमता में वृद्धि में मददगार होगा। पत्रकारिता को संरक्षण मिलेगा, पत्रकारिता की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। पत्रकारों को पत्रकारिता की गरिमा और आचरण का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम समयबद्धता का पालन करें। निर्भय और निडर होकर गरिमा के साथ पत्रकारिता करें। उन्होंने कहा कि एक अच्छी पत्रकारिता के लिए जरूरी है कि संवाद, संपर्क एवं सूत्र मजबूत हों। उन्होंने नई पीढ़ी के पत्रकारों से आग्रह किया कि वह समाज में सम्मान पाने के लिए बेहतर आचरण रखें। श्री तिवारी ने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद ने प्रेस एक्ट में बदलाव कर अपना काम कर दिया है, पत्रकारों को भी अब अपने दायित्वों का निर्वाह पूर्ण ईमानदारी के साथ करना होगा। पत्रकारों के हितों का संरक्षण एवं कल्याण राज्य शासन का दायित्व है। राज्य शासन खुले मन से पत्रकारों का सहयोग कर रही है।

भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार श्री रघुवीर तिवारी ने कहा कि तकनीकी के नए युग में न्यूज का स्वरूप भी बदल रहा है। पत्रकारिता का दायरा भी बढ़ा है। प्रसारण के तौर तरीके में भी तेजी से बदलाव आया है। तकनीकी के नए दौर में पत्रकारिता के स्वरूप में हमें अपनी मूल पत्रकारिता को नहीं खोना चाहिए। अपनी विश्वसनीयता को हर हाल में कायम रखना होगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के मूल्य में भी बदलाव आ रहा है। कार्य प्रणाली में भी बदलाव हुआ है। श्री रघुवीर तिवारी ने कहा कि नया प्रेस एक्ट नैतिक मूल्यों के संरक्षण में मददगार होगा। यह एक्ट हमारे कार्यों को सहज एवं सुविधाजनक बनाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के प्रति हमारी जवाबदेही को समझते हुए स्वयं ही अपने आचरण के मानक तय करें। आचरण के मानक किसी नियम कानून से तय नहीं होते हैं, यह मानक समाज हित में हमें ही बनाना होंगे।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री नवनीत शुक्ला ने कहा कि पहले पत्रकार एवं पत्रकारिता के एक निश्चित सिद्धांत होते थे। पत्रकारिता मिशन थी। आज इसमें नकारात्मक बदलाव आया है। पत्रकारिता में नई चुनौतियां आज हमारे सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है, इसे दिल से की जाना चाहिए। पत्रकारिता अगर दिल और दिमाग से करेंगे तो हमें सम्मान जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को जीवित रखना होगा। हमें पत्रकारिता के आचरण के मानकों का पालन भी करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रेस एक्ट में समय की जरूरत के मान से आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता ऊर्जा एवं अनुभव के साथ में निखरती है। श्री प्रवीण खारीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि नया प्रेस एक्ट पत्रकारिता को नया स्वरूप देगा। प्रेस से जुड़े लोगों का दायित्व है कि वह नए प्रेस एक्ट का उपयोग कर समाज को नई दिशा दिखाएं।

श्री खारीवाल ने कहा कि पत्रकारों को अपने आचरण में सुधार लाने की जरूरत है। समाज हित में अधिक से अधिक अपनी कलम का उपयोग करें। कार्यक्रम के प्रारंभ में संयुक्त संचालक जनसंपर्क डॉ. आरआर पटेल ने स्वागत उदबोधन देकर कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन श्री संजय लाहोटी ने किया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में पत्रकारगण मौजूद थे।

विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भरता के बिना संभव नहीं : प्रधानमंत्री

पोखरण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं के लाइव फायर और कौशल अभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के एक संयोजित प्रदर्शन का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को दोहराया और कहा कि विकसित भारत की कल्पना इसके बिना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के अभ्यास के बाद सैन्यकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम की गर्जना ही भारत की शक्ति है। हथियार और गोला-बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम 'मेक इन

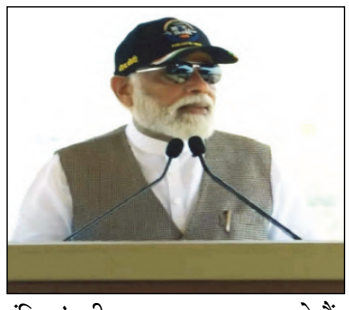

इंडिया' की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत शक्ति का उत्सव राजस्थान में हो रहा है लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। पोखरण को भारत के परमाणु हथियारों के परीक्षण स्थली के रूप में जाना जाता है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत के आत्मविश्वास और भारत के आत्मगौरव की त्रिमूर्ति का साक्षी बना है। पोखरण एक समय में भारत की परमाणु शक्ति का गवाह बना था। आज स्वदेशीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की शक्ति का गवाह बन गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की उपलब्धि पर उन्होंने कहा कि आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरीडोर बन रहे हैं। इनमें अब तक 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश हुआ है।

सम्पादकीय

प्रधानमंत्री का अरुणाचल प्रदेश दौरा चीन को खटक गया

प्रधानमंत्री का अरुणाचल प्रदेश दौरा चीन को खटक गया है। उसने भारत के समक्ष राजनयिक आपत्ति दर्ज कराई कि अरुणाचल में इस तरह भारतीय नेताओं के दौरे से दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे मामले और उलझ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है और वहां भारतीय नेताओं के दौरों को किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। चीन के इस दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने फिर दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अंग था, है और रहेगा। दरअसल, पिछले हफ्ते शनिवार को प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में बनी सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित की।

असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग को जोड़ने वाली यह सुरंग हर मौसम में आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। इससे सामरिक महत्त्व के तवांग इलाके तक हर मौसम में भारतीय सैनिकों की आवाजाही आसान हो जाएगी। करीब तेरह हजार फुट की ऊंचाई पर बनी इस सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी सुरंग माना जा रहा है। जाहिर है, इससे चीन असहज हो उठा है। तवांग तक भारतीय सैनिकों की पहुंच आसान होने का अर्थ है, चीन को बड़ी सामरिक चुनौती।

चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहते हुए अपना क्षेत्र बताता रहा है। पिछले वर्ष जब उसने भारतीय क्षेत्र की कुछ जगहों को अपने नक्शे में दिखाते हुए उनके नाम बदल दिए थे, तो उनमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल था। चीन ने अरुणाचल का नाम बदल कर जैगनान रख दिया है। इस पर भारत ने उस वक्त भी सख्त नाराजगी जाहिर की थी। कोई भी देश इस तरह किसी दूसरे देश के किसी हिस्से का नाम बदल कर उसे अपने नक्शे में शामिल कर ले, तो इससे अंतरराष्ट्रीय सीमा का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर हुए समझौते के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। वहां रहने वाले लोगों को बकायदा यहां की नागरिकता प्राप्त है। मगर चीन समय-समय पर यह जताने से बाज नहीं आता कि भारत ने अरुणाचल पर अवैध कब्जा कर रखा है। जबकि हर बार भारत ने उसके इस दावे का पुरजोर खंडन किया है।

इस बार भी उसके दावे को निराधार बता कर खारिज कर दिया गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा संबंधी समझौते को झुठलाने और वहां अस्थिरता पैदा करने की चीन की कोशिशें किसी से छिपी नहीं हैं। अक्सर उसके सैनिक सीमा पार कर भारत के अधिकार वाले हिस्से में आ जाते हैं। जब उन्हें चुनौती दी जाती है, तो वे लौट जाते रहे हैं।

करीब चार वर्ष पहले उसके सैनिक गलवान घाटी में घुस कर भारतीय सैनिकों से गुत्थमगुत्था हो गए थे। उस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक शहीद हो गए। तबसे दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन के सैन्य अधिकारी बातचीत की मेज पर आते रहे हैं। यह दिखाने का प्रयास करते रहे हैं कि वे इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं, मगर हकीकत में यह मसला अभी तक उलझा हुआ है। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर चीन कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह भारत के हिस्से वाली कई जगहों के नाम बदल कर उन्हें अपना हिस्सा बताता रहा है। मगर भारत ने उसकी विस्तारवादी नीतियों को हर समय ठोस चुनौती दी है।

बच्चों को हर हाल में बनाइए संस्कारित-पंडित प्रदीप मिश्रा

सीहोर। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा के साथ भक्ति जैसे संस्कारों का रोपण करना जरूरी है। बच्चे के अंदर संस्कार दो, कार नहीं। अगर संस्कार होंगे तो कारों की लाइन लग जाएगी। बच्चों को हर हाल में संस्कारित बनाइए।

पंडित मिश्रा सीहोर के चितावलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर एवं कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में जारी सात दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव 2024 के पांचवें दिन सोमवार को शिव महापुराण में आए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया एक लोटा जल और एक बेलपत्र सारे दुखों का नाश करता है। बेलपत्र में योग और शिव शक्ति है। जो सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं।

उन्होंने कहा कि माता-पिता, संत, गुरुजन और भगवान के भक्त की पहचान उसके जीते जी नहीं होती। उसके जाने के बाद पता चलता है कि जीवन में उनका क्या महत्व था। संत और वसंत एक जैसे हैं, संत के जीवन में आने से जीवन बदलता है तो वसंत के आने से प्रकृति बदलती हैं। जो समय भक्ति में दिया जाता है वह कभी नहीं व्यर्थ नहीं जाता, उसका लाभ जरूर मिलता है।

पंडित प्रदीप मिश्रा ने भगवान शिव के चक्रों की चर्चा करते हुए कहा कि चक्र को छोटा, लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था। सभी देवी-देवताओं के पास अपने-अपने अलग-अलग चक्र होते थे। उन सभी के अलग-अलग नाम थे। शंकरजी के चक्र का नाम भवरेंदु, विष्णुजी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यह बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्रीविष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पडने पर श्रीविष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान कर दिया। पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला। इस तरह भगवान शिव के पास कई अस्त्र-शस्त्र थे लेकिन उन्होंने अपने सभी अस्त्र-शस्त्र देवताओं को सौंप दिए। उनके पास सिर्फ एक त्रिशूल ही होता था। यह बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र था। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों दैनिक, दैविक, भौतिक के विनाश का सूचक है।

पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को विठलेश सेवा समिति के द्वारा पानी की बोतल प्रदान की जा रही है। समिति द्वारा अब तक तीस लाख से अधिक पानी की बोतल वितरण की जा चुकी है। इसके अलावा यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में लगी आधुनिक रसोई घर से सेवादारों के द्वारा भोजन प्रसादी का वितरण किया जा रहा है।

विठलेश सेवा समिति के मीडिया प्रभारी प्रियांशु दीक्षित ने बताया कि कुबेरेश्वरधाम पर हर रोज लाखों की संख्या में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु कथा का श्रवण करने पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु तो ऐसे है जो पैदल चलकर की भी धाम पर पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक दर्जन से अधिक मनावर धार से धाम पर करीब 325 किलोमीटर पैदल चलकर आए श्रद्धालुओं का कहना है कि यह उनकी तीसरी यात्रा है और वह झंडा लेकर हर साल पैदल धाम पर आते है। मनावर के रहने वाले नारायण राजपूत ने बताया कि पहली बार तो हम दो लोग ही कथा का श्रवण करने आए थे, इस बार एक दर्जन क्षेत्रवासी हमारे साथ है, बाबा ने हमारी झोली भर दी है। इन श्रद्धालुओं का गुरुदेव पंडित मिश्रा ने सम्मान किया।

सुधा मूर्ति का नॉमिनेशन राज्यसभा में

सुधा मूर्ति का नॉमिनेशन राज्यसभा में हुआ है। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ट्विटर पर की है। सुधा मूर्ति अब राज्यसभा में बैठेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अपने कार्यों से चोंकाते रहते हैं, वह अपने निर्णय से भविष्य के संकेत भी देते हैं। क्या नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के कैबिनेट में सुधा मूर्ति महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगी। कुछ भी हो सकता है। मोदी के दूसरे मंत्रिमंडल में जिस तरह प्रधानमंत्री एस जयशंकर को विदेश मंत्री और अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया था ठीक उसी तरह सुधा मूर्ति भी अगले कैबिनेट में देखें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

सुधा मूर्ति 78 वर्ष की उम्र में भी अपने सामाजिक कार्यों और महिला उत्थान के लिए सदैव चर्चा में रहती है। वे infosys की cofounder है उनकी networth ||z crore है। उनका sense of humour बहुत अच्छा है। अक्सर उनको कहते सुना जाता है कि मैंने अपने हस्बैंड Narayan murthy को बिजनेसमैन और मेरी बेटी Akshta murthy ने अपने हस्बैंड Rishi sunak को Prime minister of UK बना दिया। सुधा मूर्ति ने अपने हस्बैंड नारायण मूर्ति को इंफोसिस कंपनी शुरू करने के लिए 10000 का लोन दिया था। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए वे आज भी सादा-साधारण जीवन यापन कर रही है। उन्हें त्यौहार पर घर में बैठकर खाना बनाते हुए देखा जा सकता है। सुधा मूर्ति वर्षों से विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुखरता से अपनी बात रखने के लिए प्रसिद्ध है। कर्णाटक के सभी स्कूल में उन्होंने लाइब्रेरी खोली है। सुधा मूर्ति ने कई बेस्ट सेलर पुस्तक लिखी है। उनकी लिखी 30 से अधिक पुस्तकों में डोलर बहू आदि लोकप्रिय पुस्तक है। सुधा मूर्ति पर लिखे गए आर्टिकल्स और वीडियो से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। Sudha murthy कीवर्ड ही बन गया है।

राज्यसभा में नॉमिनेशन का मतलब

हमारे संविधान निर्माता में जब संविधान की रचना की तब तय किया कि संसद में दो सदन होंगे। एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस अप्पर हाउस राज्य सभा को कहा जाता है और लोअर हाउस को लोकसभा। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते है। 250 सीट में से 12 सीट पर राष्ट्रपति देश के प्रबुद्ध साहित्य संस्कृति एवं अचीवर्स का नॉमिनेशन करते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि इस फील्ड से आने वाले लोग राजनीति में उतने पारंगत नहीं होते, इसलिए वे चुप रहते है, दर्शक बनकर ही अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। ऐसे सदस्य कभी राज्यसभा में भाषण करते नजर नहीं आते। राज्यसभा में नरगिस, हेमा मालिनी, जयाप्रदा और जया बच्चन सहित कई फिल्म स्टार रहे है। कई वैज्ञानिकों, साहित्यिक सांस्कृतिक विभूतियों का भी नॉमिनेशन किया जाता रहा है। लेकिन सुधा मूर्ति राज्यसभा में चुप बैठने वालो में नहीं है।

संसद और विधानसभाओं में वोट या भाषण के लिए रिश्वत के लिए मुकदमा का सामना करना पड़ सकता है-एससी

संसद के सदस्यों (सांसदों) और विधान सभाओं के सदस्यों (विधायकों) को छूट की अनुमति देने वाले अपने 1998 के फैसले को पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि विधायकों को संसद और विधानसभाओं में वोट भाषण के लिए रिश्वत लेने के लिए आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। अपने सर्वसम्मत फैसले में, मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि सांसद और विधायक वोट देने या किसी विशेष तरीके से बोलने के लिए रिश्वत में शामिल होने के लिए आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाने से छूट का दावा नहीं कर सकते हैं।

पीठ का कहना है

हम पीवी नरसिम्हा (मामले) में फैसले से असहमत हैं। पीवी नरसिम्हा मामले में फैसला, जो विधायकों को वोट देने या भाषण देने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने से छूट देता है, के व्यापक प्रभाव हैं और इसे खारिज कर दिया गया है। छूट के लिए ऐसा दावा यह परीक्षण पूरा करने में विफल रहता है कि विधायी कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसी छूट आवश्यक है या नहीं।

अनुच्छेद 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है क्योंकि रिश्वतखोरी में लिप्त सदस्य एक आपराधिक कृत्य में शामिल होता है जो वोट देने या विधायिका में भाषण देने के कार्य के लिए आवश्यक नहीं है। रिश्वत का अपराध रिश्वत लेने पर स्पष्ट हो जाता है अवैध परितोषण का। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वोट या भाषण बाद में दिया गया है या नहीं। अपराध उस समय पूरा होता है जब विधायक रिश्वत स्वीकार करता है। पिछले साल अक्टूबर में, पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने दलील दी कि सांसदों और विधायकों को दी गई छूट उन्हें रिश्वत लेने के लिए आपराधिक मुकदमे से नहीं बचाएगी, उन्होंने कहा कि वोट देने के मामले में प्रदर्शन सौदेबाजी का हिस्सा है। या भाषण प्रासंगिक नहीं है क्योंकि अपराध सदन के बाहर किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ के पास पीवी नरसिम्हा राव बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में 1998 के फैसले को इंक्यूरियम के अनुसार वर्गीकृत करने का विकल्प हो सकता है, जो रोकथाम की वैधानिक योजना को ध्यान में रखने में विफल रहा। भ्रष्टाचार अधिनियम के बजाय यह घोषणा करें कि यह एक अच्छा कानून नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में अपने 1998 के फैसले में, शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी थी कि संविधान के अनुच्छेद 105 की पृष्ठभूमि के खिलाफ, सांसदों को संसद में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में आपराधिक मुकदमा चलाने से छूट प्राप्त है। इसी तरह की छूट राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अनुच्छेद 194(2) द्वारा प्रदान की गई है। 2019 में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्य सीता सोरेन द्वारा शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद उठने वाले प्रश्न के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास विचार के लिए भेज दिया। 2014 में 2012 के राज्यसभा चुनावों में एक विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के लिए उनके खिलाफ स्थापित आपराधिक आरोपों को रद्द करने की मांग की गई।

कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक भाजपा में शामिल

भोपाल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को कांग्रेस के 2 बड़े नेता शिवदयाल बागरी और अरुणोदय चौबे ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। वंही भाजपा के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी भी भोपाल पहुंचे थे और अटकलें थीं कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।

लेकिन पूर्व विधायक जोशी सोमवार को भाजपा में शामिल नहीं हुए। अटकलों के बारे में पूछे जाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, लोग भारतीय जनता पार्टी में आते रहेंगे और परिवार बढ़ता रहेगा।

कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता अरुणोदय चौबे और शिवदायल बागरी को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अंगवस्त्र पहनकर भाजपा की सदस्यता दिलाई है। दोनों नेताओं के साथ कई कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए हैं।

कमलनाथ के करीबी और सागर जिले की खुरई सीट से विधायक रहे अरुणोदय चौबे के साथ पन्ना के गुनौर से कांग्रेस विधायक रहे शिवदयाल बागरी भाजपा में शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है की अरुणोदय चौबे को कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा भी थी। लेकिन उससे पहले वो बीजेपी के हो गए।

इधर अलीराजपुर जिले में 6 बार सरपंच और 3 बार जनपद सदस्य रहे भील नेता कमरू भाई ने भी भाजपा की सदयस्ता ले ली है। वहीं मिल रही सूचना के आधार पर भाजपा के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी भोपाल पहुंच चुके है और उनके वापस भाजपा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है की भाजपा के पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने 6 मई 2023 को कांग्रेस जॉइन कर ली थी।

शिवदयाल बागरी गुनौर से 2018 में कांग्रेस के विधायक रहे और राइ डांस से चर्चा में आए थे। साल 2023 के चुनाव में शिवलाल बागरी का टिकट काट कर जीवन लाल सिद्धार्थ को दे दिया था। बताया जा रहा है कि पिछले चुनाव में अपना टिकट कटने से शिवदयाल बागरी कांग्रेस से नाराज़ चल रहे थे। वंही गुनौर सीट से सपा की विधानसभा प्रत्याशी रहीं अमिता बागरी ने भी तीन दिन पहले बीजेपी में घर वापसी की है।

एमपी की सागर जिले की खुरई सीट से कांग्रेस के विधायक रहे अरुणोदय चौबे विधानसभा चुनाव में खुरई सीट से मुख्य दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने चुनाव के कुछ महीने पहले ही कांग्रेस पार्टी में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने खुरई में रक्षा राजपूत को प्रत्याशी बनाया था। इस लोकसभा चुनाव में अरुणोदय सागर सीट से कांग्रेस के मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए अपनी उम्मीदवारी से कदम पीछे खींच लिए थे। सोमवार को भोपाल पहुंचकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है। चौबे की लोकसभा उम्मीदवारी से सरेंडर किए जाने के बाद अब कांग्रेस को नए सिरे से सागर सीट पर मजबूत उम्मीदवार खोजने की चुनौती बढ़ गई है।

देवास जिले की हाटपिपलिया से पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने 6 मई 2023 को कांग्रेस का हाथ थामा था। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन शिवराज सरकार पर अपने पिता स्वर्गीय कैलाश जोशी के स्मारक बनवाने में उदासीनता बरतने और खुद की उपेक्षा के आरोप लगाकर बीजेपी छोड़ दी थी। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी जॉइन कर ली थी। इस दौरान वह अपने साथ पिता और पूर्व सीएम कैलाश जोशी का फोटो लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला था।

निगम आयुक्त ने ठेकेदार एसोसिएशन के साथ बैठक की

उज्जैन। नगर निगम की वित्तीय स्थिति अनुसार ठेकेदारों का भुगतान किया जाएगा। शहर विकास में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है शहर विकास को बेहतर बनाने के लिये निर्माण कार्यों के टेंडर में भागीदारी करते हुए शहर विकास में आप सहयोग करे। यह बात निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक ने नगर निगम ठेकेदार एसोसिएशन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में कही। सोमवार को निगम ठेकेदार एसोसिएशन के सदस्य निगम आयुक्त से भुगतान एवं अन्य समस्याओं के संबंध में चर्चा हेतु मिले। ठेकेदारों द्वारा बकाया भुगतान की जानकारी देते हुए ठेकेदारों को भुगतान किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक द्वारा एसोसिएशन के सदस्यों को जल्द भुगतान किए जाने के लिए आश्वस्त किया गया साथ ही अन्य जो समस्याएं है उनका भी समाधान किए जाने के लिए कहा गया।

बैठक में अपर आयुक्त श्री दिनेश चौरसिया, श्री आर.एस. मंडलोई, ठेकेदार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री निलेश अग्रवाल, सर्वश्री तपन वैष्णव, पंकज यादव, विवेक सिंह ठाकुर, देवेन्द्र गेहलोत, सुरेन्द्र अग्रवाल, पंकज भाटी, अरविंद यादव उपस्थित रहे।

सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में लखपति दीदियों को किया सम्मानित

इंदौर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के तहत स्व सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण आजीविका मिशन समूह की सदस्य लखपति दीदियों व नमो ड्रोन समूह की प्रशिक्षित सदस्यों को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने समूह सदस्यों के जीवन स्तर में आये परिवर्तनों के साथ ही कृषि के क्षेत्र में नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से भविष्य में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तनों के बारे में अवगत कराया।

इन्दौर जिले में मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विभिन्न ग्रामों में गठित स्व सहायता समूह सदस्यों द्वारा संकुल स्तरीय संगठन स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम का चार हजार से अधिक समूह सदस्यों द्वारा लाईव प्रसारण ग्राम स्तर पर देखा गया। जिला मुख्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में उपरोक्त कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी विशेष रूप से शामिल हुए।

प्रधानमंत्री मोदी की मंशानुरूप जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्व सहायता समूह सदस्य जो विभिन्न आय अर्जक गविधियों में शामिल होकर लखपति दीदी की श्रेणी में आ रही है उनसे सांसद शंकर लालवानी द्वारा चर्चा की गई। लालवानी ने कलारिया से

रामकली बामनिया, सिंहासा से संतोष राठौर, सिंदौडा से कोमल सिसोदिया, नैनोद से नीतू एवं फुलकराडिया से अनिता परिहार को लखपति दीदी होने पर सम्मानित किया। जिले के समस्त संकुल स्तरीय संगठनों में उपस्थित समूह सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का लाईव प्रसारण देखा गया व संकुल स्तर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों की उपस्थितियों में समूह से जुड़कर स्वयं के जीवन में आये परिवर्तनों से उपस्थित अतिथियों को अवगत करा कर अपने अनुभव साझा किये। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत जिला इन्दौर से पूर्व प्रशिक्षित समूह सदस्य रचना पटेल, ग्राम खुडेल द्वारा ममता ठाकुर, भोपाल से उक्त कार्यक्रम में ड्रोन उडाकर प्रतिभाग किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिंगल क्लिक से कार्यक्रम के दौरान जिले के 68 समूहों को संकुल स्तरीय संगठनों के माध्यम से राशि 68 लाख रुपये का सामुदायिक निवेश निधि एवं 68 समूहों को राशि 13 लाख 68 हजार का चक्रिय निधि(आर. एफ.) जारी किया गया। साथ ही विभिन्न बैंकों के माध्यम से भी स्व सहायता समूहों को बैंक ऋण राशि का वितरण किया गया।

निःशुल्क शिविर में 7,700 से अधिक नागरिकों ने लिया स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ

इंदौर। संभाग के बुरहानपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र खकनार सांई मंदिर परिसर में निःशुल्क वृहद स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 7 हजार 700 से अधिक नागरिकों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लिया।

वृहद स्तर पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर में गर्भवती महिलाओं के लिए पंजीयन काउंटर, शुगर व ब्लड जांच सुविधा, हिमोग्लोबिन टेस्ट, सोनोग्राफी सहित अन्य विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उपचार किया गया। शिविर में सिकल सेल एनीमिया जांच, ईसीजी, मेडिसिन विशेषज्ञ एवं अन्य मेडिकल विशेषज्ञों ने जिला प्रशासन के सहयोग से शिविर में आये नागरिकों को लाभान्वित किया। शिविर का उद्देश्य एक ही जगह निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधायें दूरस्थ अंचलों के नागरिकों को मुहैया कराना था।

क्षेत्रीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटील एवं नेपानगर विधायक मंजू दादू ने शिविर का जायजा लिया। स्वास्थ्य शिविर में सांसद पाटील ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को 5 लाख रूपये तक निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति आयुष्मान योजना का लाभ अवश्य लें। नेपानगर विधायक सुश्री मंजू दादू ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बुरहानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाराम मार्को एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत सीईओ सृष्टि देशमुख, जनपद पंचायत खकनार सीईओ वंदना कैथल, चिकित्सक, अधिकारीगण व विभिन्न क्षेत्रों से आये बड़ी संख्या में नागरिकजन उपस्थित थे।

स्वास्थ्य शिविर के प्रभारी डॉ. देव कृष्ण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि निःशुल्क वृहद स्वास्थ्य शिविर में मेडिकल कॉलेज इंदौर के 75 चिकित्सा विशेषज्ञ और मेडिकल कॉलेज खंडवा के 62 चिकित्सा विशेषज्ञों ने अपनी सेवायें दी। इस दौरान शिविर में नागरिकों का सहजता से उपचार करते हुए उन्हें दवाईयां वितरित की गई तथा आवश्यक समझाईश भी दी गई। बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देशानुसार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में नागरिकों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया। शिविर में दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर, एम्बुलेंस, व्यवस्थित पंजीयन काउंटर, दवाईयों का वितरण, विभागीय स्टॉल, ब्लड डोनेशन कैंप सहित सभी 126 काउंटरों को पृथक-पृथक करते हुए नंबरिंग की गई। जिससे आने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा।

स्वास्थ्य शिविर में आये ग्राम सीवल के सेवक दांगोड़े बताते हैं कि, मेरी आंखों में इंफेक्शन हो गया था। आंखों से देखने में बहुत परेशानी हो रही थी। धुंधला सा दिखाई दे रहा था।

शिविर में मेरी आंखों की अच्छे से जांच हुई। डॉक्टर द्वारा उचित देखभाल, मेडिसीन उपलब्ध कराने के साथ-साथ सभी का अच्छा सहयोग मिला। ग्राम सिरपुर के रोशन खान ने शिविर के माध्यम से अपने बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य का उपचार कराया। उन्होंने कहा कि, शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर ने निःशुल्क मेरे बच्चे का उपचार किया एवं दवाईयां भी उपलब्ध करवाई है। सीएमएचओ डॉ.राजेश सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि, निःशुल्क वृहद स्वास्थ्य शिविर का करीबन 7 हजार 700 से अधिक नागरिकों ने लाभ लिया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में कार्डियोलॉजी, न्युरोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसीन, जनरल फिजिशन, जनरल एण्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जनरल सर्जरी, शिशु रोग, बाल हृदय रोग, गेस्ट्रोलॉजी, नाक कान गला रोग, रेडियाथेरेपी, रेडियोडायग्नोसिस, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, दन्त रोग, मानसिक रोग, चर्म रोग, क्षय रोग जैसे विभागों के चिकित्सकों द्वारा मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार करते हुए दवाईयां वितरित की गई।

मामूली विवाद में 11वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या

इंदौर। शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में सोमवार की रात मामूली विवाद पर एक कक्षा 11वीं के छात्र की पड़ोस में रहने वाले परिवार ने चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रात को उसके घर का गेट बंद होने पर वह लोडिंग का सहारा लेकर गेट पर चढ़ रहा था। इस पर पड़ोसियों ने आपत्ति ली और उसे चाकू मार दिए। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने हितेश प्रजापति, महेंद्र योगी, हर्ष योगी, अशोक चौहान, अजय पंडित के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, राजबाग कालोनी में रहने वाले छात्र कोटेश्वर कक्षा 11वीं में पढ़ता है। मंगलवार को उसका पेपर था। वह सोमवार शाम से अपने पेपर की तैयारी कर रहा था। रात को वह अपने मित्रों से थोड़ी देर के लिए मिलने गया था। वह मित्रों से मिलकर घर आया तो गेट पर ताला लग गया था। वह पड़ोसी के लोडिंग का सहारा लेकर भीतर जाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच पड़ोस में रहने वाले हितेश प्रजापति से उसका विवाद हो गया। उसके साथ परिवार के अन्य लोग भी आ गए और कोटेश्वर से मारपीट करने लगे।

इसी दौरान हितेश ने चाकू से कोटेश्वर के सीने और हाथ पर वार कर दिया। बीच-बचाव करने आया कोटेश्वर का रिश्तेदार कुलदीप भी चाकू लगने से घायल हो गया। परिजन दोनों को अस्पताल ले गए, लेकिन देर रात कोटेश्वर की मौत हो गई।

कार पर पलट गया लोडेड ट्रक, घायल महिला की मौत

इंदौर। इंदौर जिले के कम्पेल इलाके में बच्चों की पैरेंट्स मीटिंग में शामिल होने के बाद घर लौट रहे हार्डवेयर व्यापारी की कार पर ओवरलोड ट्रक पलट गया।

हादसे में तीन बच्चों सहित सात लोग कार में दब गए। देर रात सभी घायलों को इंदौर लाया गया, जहां उपचार के दौरान देर रात हार्डवेयर व्यापारी की भाभी अंजू (38) मौत हो गई। अन्य घायलों का उपचार किया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक मुर्गीदाना की बोरियों से भरा हुआ ट्रक पेडमी, खंडेल होकर डबल चौकी की ओर जा रहा था। इसी दौरान उदयनगर (देवास) निवासी सुमित जायसवाल (35) वेगनआर कार से कम्पेल की तरफ जा रहे थे। कार में सुमित की पत्नी पूर्णिमा (32), बेटा व्योमेश (8), बेटी मिताली (12), मां सविता (55), भाभी अंजू (38) पति अनिल जायसवाल और भतीजी काव्या (9) भी थी। सभी लोग बच्चों के स्कूल में पैरेंट्स टीचर मीटिंग में शामिल होकर लौट रहे थे। तभी ये हादसा हो गया।

पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से ट्रक में लदी बोरियां उतारी, जिसके बाद क्रेन से ट्रक उठाया गया। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसकी बॉडी कॉटकर घायलों को बाहर निकाला गया। सबसे पहले 15 मिनट के भीतर तीनों बच्चों को बाहर निकाला गया। हालांकि कुछ लोग सवा घंटे तक अंदर ही दबे रहे और दर्द से कराहते रहे।

मप्र को मिली चौथी वंदे भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर की शुरुआत

भोपाल। मध्यप्रदेश को चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। यह मध्य प्रदेश में चलने वाली चौथी वंदे भारत ट्रेन है। इससे पहले पीएम मोदी मध्यप्रदेश को तीन वंदे भारत ट्रेन की सुविधा प्रदान कर चुके हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने देशभर में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही 85 हजार करोड़ से अधिक की छह हजार रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे 100 साल के रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया। उन्होंने कहा कि आज जो लोकार्पण हुआ है, वह वर्तमान के लिए और जो शिलान्यास हुआ है वह उज्ज्वल भविष्य के लिए है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने रेल को अलग बजट से निकालकर भारत सरकार के बजट में डाल दिया। इससे रेलवे को विकास के लिए अधिक राशि मिलने लगी। उन्होंने कहा कि 700 से ज्यादा स्थान पर लाखों लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। विकसित भारत के लिए हो रहे नव निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। इस 2024 में अब तक 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। आज रेलवे के 85,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। भोपाल मुख्य रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के ध्येय वाक्य के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश के विकास के लिए रेलवे का विकास महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। देश के मध्य में स्थित हमारा मध्यप्रदेश, रेलवे अधोसरंचना विकास के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर है। मोदी ने वीसी के माध्यम से विभिन्न रेल परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इनमें भोपाल मंडल के अंतर्गत तीन जिलों में स्थित पांच स्टेशनों पर (बीना-1,भोपाल-3,रानी कमलापति-3,नर्मदापुरम-2 एवं इटारसी-2) पर 72.5 लाख रुपये की लागत से तैयार कुल 11 एक स्टेशन एक उत्पाद स्टालों का लोकार्पण किया गया। वहीं, बीना स्टेशन पर 12.5 लाख रुपये की लागत से तैयार एक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र और एक करोड़ की लागत से तैयार बुदनी माल गोदाम का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसके अलावा रामगंज मंडी-भोपाल नयी रेल लाइन के अंतर्गत निशातपुरा डी केबिन से संत हिरदाराम नगर तक के रेल लाइन खंड (9.86 कि.मी.) का लोकार्पण किया गया है, जिकी लागत करीब 65 करोड़ रुपये है। वहीं, भोपाल के बैरागढ़ में वंदे भारत ट्रेन के मेंटनेंस के लिए कोचिंग काम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इस काम्प्लेक्स में एक साथ 10 वंदे भारत ट्रेन के मेंटनेंस का काम किया जा सकेगा।

पूरा देश मोदी का परिवार है : शिवराज सिंह चौहान

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, लेकिन मोदी कहते हैं कि सारा देश मेरा परिवार है, सारे भाई-बहन मेरा परिवार है, सारे बेटा-बेटी मेरा परिवार है। इंडी गठबंधन के लोग केवल अपने बेटा-बेटी का विकास करते हैं। स्टालिन, उदयनिधि के लिए है, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के लिए है, लालू यादव, तेजस्वी यादव के लिए है। यह अगर हैं तो केवल अपने बेटा-बेटियों के लिए, लेकिन मोदी तो सारे देश के लिए हैं। अगर डीएमके जीतेगी तो स्टालिन के परिवार का विकास होगा और भाजपा जीतेगी तो पूरे तमिलनाडु का विकास होगा, भारत की जनता का विकास होगा।

मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान सोमवार को तमिलनाडु के अराक्कोनम और कांचीपुरम लोकसभा में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक और भाजपा बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने वैल्लोर के प्रसिद्ध श्रीलक्ष्मी नारायणी गोल्डन टेंपल में पूजा-अर्चना की और देश व प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। साथ ही मंदिर परिसर में पौधरोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तमिलनाडु आकर अत्यंत प्रसन्न हूं, यहां की जनता में प्रधानमंत्री के लिए अद्भुत प्रेम है। तमिलनाडु के विकास और यहां की जनता के कल्याण के लिए पिछले 10 सालों में पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि मोदी सरकार ने दी है। शिवराज ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। अगर विकास के काम गिनाऊंगा तो कई घंटे लग जाएंगे। हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मेडिकल कॉलेजेस इतने विकास के काम हुए है कि कोई कभी नहीं सोच सकता था। मोदी सरकार की विकास की ये गंगा, तमिलनाडु में भी बह रही है। इसके बाद भी तमिलनाडु सरकार मोदी जी का विरोध ही करती रहती है। उन्होंने कहा कि पूरा भारत एक है, हम सब भारत मां के लाल भेदभाव का कहां सवाल। मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को तमिल संस्कृति से बेहद प्रेम हैं, उन्होंने तमिल-काशी संगमम किया। हमारे पवित्र सेंगोल को नए पार्लियामेंट में स्थापित किया। मोदी हमारी तमिल जीवन मूल्य परंपरा और महापुरुषों का आदर करते हुए पूरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। वे जहां भी जाते हैं वहां तमिल संस्कृति व परंपराओं के बारे में बताते हैं और सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में तमिल भाषा में अगर बोले तो मोदी ही बोले हैं। तमिल भाषा में बोलने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सोचो अगर कोरोना के दौरान मोदी नहीं होते तो क्या होता..? पहले किसी महामारी की वैक्सीन कई वर्षों तक नहीं बनती थी। रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान बनाते थे और हम वैक्सीन के लिए उनपर निर्भर होते थे लेकिन अब मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नौ महीने के अंदर एक नहीं दो-दो वैक्सीन बन गई और 200 करोड़ डोज भारतीयों के लगे और 100 करोड़ से ज्यादा दुनिया के बाकी देशों को लगाए थे। उनकी जान बचाने का काम मोदी ने किया। डीएमके और कांग्रेस के नेता, इंडी गठबंधन के नेता पहले वैक्सीन का मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है मत लगवाओ, लेकिन बाद में अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने भी मोदी वैक्सीन लगवाई। वो अगर आज जिंदा है तो मोदी वैक्सीन के कारण जिंदा हैं, यह चमत्कार नरेन्द्र मोदी ने किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विश्वास नहीं होता कि एक व्यक्ति इतना काम कैसे कर सकता है। मैं कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा। यूपीए की सरकार थी जब में कहीं भी जाता तो भारत का कहीं मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी। भारत को लोग घोटालों के देश के रूप में जानते थे कहीं हमको सम्मान नहीं मिलता था लेकिन जब से मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, चारों तरफ भारत माता की जय हो गई है। पूरी दुनिया आज मोदी-मोदी बोल रही है। जब पूरी दुनिया मोदी-मोदी कहती है तो वो सम्मान केवल नरेन्द्र मोदी का नहीं होता कार्यकर्ता भाइयो-बहनों और हम सबका होता है, 140 करोड़ भारतवासियों का होता है। मोदी एक व्यक्ति नहीं, मोदी एक संस्था हैं। मोदी साधारण इंसान नहीं, एक महान- परम आत्मा है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रगति उसके प्रभावशाली अनुसंधान आउटपुट और नवाचार से जाहिर होती है

भारत की प्रगति के चित्रपट में, बीता दशक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की कहानी का जीवंत सूत्रधार रहा है। यह अवधि बदलाव को दर्शाती है, जहां शैक्षणिक संस्थान केवल ज्ञान के मंदिर भर नहीं रहे, बल्कि शिक्षण और समाज को समान रूप से आकार देते हुए नवाचार की आजमाइश बन गए। वैश्विक कस्तर पर हो रहे परिवर्तनों के बीच, भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है। धूप में कमल की तरह खिल रहा है। यह केवल संख्या में वृद्धि का ही नहीं, बल्कि क्षमता की जागृति का भी प्रतीक है, जो भविष्य को ज्ञान, कौशल और विजन के सूत्र से बुन रहा है। अब जबकि भारत विश्व के लिए मानव संसाधनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनने की दिशा में क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहा है, हम भविष्य के संभावित घटनाक्रमों का अनुमान लगाते हुए बीते दशक में उच्च शिक्षा के परिदृश्य में भारत द्वारा की गई प्रगति पर विचार करते हैं।

संभावनाओं से भरपूर दशक की शुरुआतः भारतीय उच्च शिक्षा परिदृश्य वर्ष 2013-14 में बड़े बदलाव की ओर अग्रसर होने के कारण एक अहम पड़ाव पर था। हालांकि उसकी प्रगति स्पष्ट थी, लेकिन पहुंच बढ़ाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण चुनौतियां यथावत थीं।18-23 वर्ष आयु वर्ग के लिए लगभग 23 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के साथ पहुंच और नामांकन सीमित थे, जिनसे नितांत क्षेत्रीय असमानताएं एवं सामाजिक-आर्थिक बाधाएं प्रकट होती थीं। 723 विश्वविद्यालयों और 36,634 कॉलेजों सहित संस्थागत परिदृश्य, बुनियादी ढांचे की बाधाओं से विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में जूझ रहा था। वित्त पोषण एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था। जीडीपी के 3.84 प्रतिशत के कुल शैक्षिक व्यय में से उच्च शिक्षा को सीमित आवंटन प्राप्त हो रहा था।

यद्यपि एमओओसी जैसी डिजिटल पहल (एनपीटीईएल के एक प्रमुख उपलब्धि होने के नाते) उभर चुकी थी लेकिन असमान इंटरनेट कनेक्टिविटी और ढांचागत चुनौतियों के कारण उसकी पहुंच सीमित थी। ऑनलाइन शिक्षा, हालांकि संभावनाएं दर्शा रही थी, लेकिन मुख्यधारा के शिक्षण अनुभवों में पूर्ण एकीकरण के सामर्थ्य के साथ वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। इन चुनौतियों के बावजूद, वर्ष 2013-14 आत्मनिरीक्षण और सुधार का दौर भी रहा। इसने भविष्य में आगे बढ़ने की महत्वपूर्ण प्रेरणा का कार्य किया, जहां भारतीय उच्च शिक्षा पहुंच के अंतर को पाटने, गुणवत्ता बढ़ाने और परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों को अपनाने का प्रयास करेगी।

प्रमुख सुधार और पहलः 2014 के बाद के वर्ष भारतीय उच्च शिक्षा को परिवर्तनकारी पथ पर आगे बढ़ाने की दिशा में हुए ठोस प्रयासों के साक्षी रहे। शिक्षा तक पहुंच को व्यापक बनाने, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने और तकनीकी प्रगति को अपनाने के प्रति लक्षित सुधारों और पहलों ने इस परिदृश्य को नया आकार दिया।

नए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की विशेषकर वंचित क्षेत्रों में स्थापना से संस्थागत नेटवर्क में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। साथ ही श्रेयस योजना, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा योजना, सब्सिडी के माध्यम से छात्र ऋण को किफायती बनाने के प्रयास (केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना 2009 को मजबूत करना) और क्रेडिट गारंटी फंड आवंटन (सीसीएफ योजना 2015) करने आदि जैसे लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के साथ हाशिये पर मौजूद समुदायों तक इस पहुंच का विस्तार हुआ और देश भर में महत्वकांक्षाओं को प्रेरणा मिली।

एआईएसएचई वर्ष 2021-22 के अनुसार, उच्च शिक्षा में नामांकन वर्ष 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 4.33 करोड़ हो गया। जीईआर वर्ष 2014-15 में 23.7 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 28.4 हो गया, महिला जीईआर वर्ष 2014-15 में 22.4 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 28.5 हो गया। इस विस्तार के परिणामस्वरूप लाखों युवा उच्च शिक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें पहले से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 एक परिवर्तनकारी रोडमैप के रूप में उभरी है, जिसमें बहु-विषयक शिक्षा, कौशल विकास और उद्योग भागीदारी पर जोर दिया गया है। इस मूलभूत बदलाव का उद्देश्य स्नातकों को उपयुक्त कौशल से लैस करना और तेजी से विकसित हो रहे नौकरी बाजार में रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है। केवल मेट्रिक्स के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि एनईपी ने, भारत में शिक्षा परिदृश्य को मौलिक रूप से फिर से परिभाषित करने के अपने प्रयासों की बदौलत इस क्षेत्र में हितधारकों के भीतर प्रेरणा और उत्थान की भावना जगाई है।

विश्वविद्यालयों ने पाठ्यक्रम में संशोधन को अपनाया, लचीली क्रेडिट प्रणाली, पसंद-आधारित पाठ्यक्रम और उद्योग के अनुरूप विशेषज्ञता की शुरुआत की। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के अग्रणी संस्थानों के साथ सहयोगपूर्ण अनुसंधान संबंधी पहल समृद्ध हुई, जिससे वैश्विकक मंच पर भारत के अनुसंधान आउटपुट को बढ़ावा मिला। शिक्षक एवं शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, अटल एफडीपी आदि जैसे शिक्षक प्रशिक्षण प्रयासों का संकाय विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वयं (जिसे वर्ष 2016 में पाठ्यक्रमों के संदर्भ में विस्तारित और समृद्ध किया गया) और एमओओसी जैसे डिजिटल शिक्षा प्लेटफार्मों के उदय ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में क्रांति ला दी। ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों ने विकल्पों का और अधिक विस्तार किया। राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना परिवर्तनकारी हो सकती है। देश भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर केंद्रित डिजिटल इंडिया और भारतनेट जैसी पहल ने डिजिटल शिक्षण उपकरणों को व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रगति उसके प्रभावशाली अनुसंधान आउटपुट और नवाचार से भी जाहिर होती है। जैसा कि यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन की 2022 की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैज्ञानिक प्रकाशनों के क्षेत्र में भारत 2010 में वैश्विकक स्तर पर सातवें स्थान से लंबी छलांग लगाते हुए वर्ष 2020 में तीसरे स्थान पर रहा।

वर्ष 2017 और वर्ष 2022 के बीच अनुसंधान आउटपुट में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वैश्विकक औसत से अधिक रही। इस अवधि में 1.3 मिलियन अकादमिक पेपर और 8.9 मिलियन उद्धरण देखे गए। नवाचार में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक पेटेंट फाइलिंग में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

निष्कर्ष-बीते दशक में भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र ने केवल वैश्विकक प्रवृत्तियों के साथ तालमेल ही नहीं बनाए रखा है, बल्कि अकसर उनका मार्ग भी प्रशस्त किया है। पर्याप्त नीतिगत सुधारों और उन्नत तकनीकी उपकरणों के एकीकरण के माध्यम से, युवा, गतिशील भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने की नए सिरे से कल्पना की गई है। आंकड़ों में प्रगति स्पष्ट होने के बावजूद, समान पहुंच, गुणवत्ता में सुधार और विविध अनुसंधान क्षेत्रों को बढ़ावा देने जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। शैक्षिक परिवर्तन की इस उल्लेखनीय यात्रा को बनाए रखने और इसमें तेजी लाने के लिए निवेश, नीतिगत सुधार और नवाचार के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता आवश्यक है।

अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण

नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सोमवार को देश में ही विकसित अग्नि-5 मिसाइल, मिशन दिव्यास्त्र का पहला सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (एमआईआरवी) तकनीक पर आधारित मिसाइल विकसित करने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक साथ अनेक स्थानों पर मुखास्त्र का इस्तेमाल कर सकती है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस परियोजना में नारी शक्ति की बड़ी भूमिका है क्योंकि इसकी निदेशक एक महिला वैज्ञानिक है। यह प्रणाली स्वदेशी एवियोनिक्स प्रणालियों और उच्च क्षमता वाले सटीक सेंसर पैकेजों से सुसज्जित है। यह क्षमता भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति का प्रतीक है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अग्नि-5 मिसाइल के पहले सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों पर गर्व है।

उज्जैन-जावरा के बीच 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाइवे के निर्माण की स्वीकृति

उज्जैन। शहर को जावरा स्थित एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज से जोड़ने के लिये 102.80 किमी लम्बे ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाइवे के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है. इस परियोजना का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हाइब्रिड एनयूटी आधार पर होगा। परियोजना की लागत 5 हजार 17 करोड़ 22 लाख रूपए है। परियोजना पर 17 वर्षों में कुल व्यय 5 हजार 17 करोड़ 22 लाख रूपए में से 557 करोड़ रूपए का भुगतान सड़क विकास निगम और 4460 करोड़ रूपए का भुगतान राज्य बजट से किया जायेगा। इस मार्ग पर 7 बड़े पुल, 26 छोटे पुल, 270 पुलिया, 5 फ्लाई ओवर, 2 रेलवे ओवरब्रिज बनाये जाएंगे।

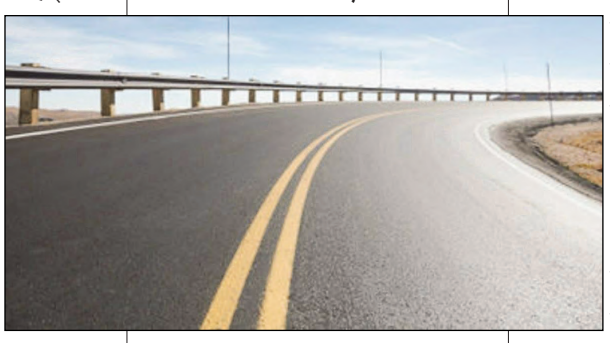

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिल्ली एवं मुम्बई के मध्य 8 लेन एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। इस राजमार्ग की 247 कि.मी. लम्बाई राज्य के मंदसौर, रतलाम एवं झाबुआ जिलों से गुजरता है। एक्सप्रेस-वे के इस भाग में 7 स्थानों पर एक्सप्रेस-वे से जुडने के लिये इंटरचेंज दिये गये हैं। इनमें से एक इंटरचेंज जावरा के पास भूतेड़ा पर स्थित है। क्षेत्र के औद्योगिक विकास एवं अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार को दृष्टिगत रखते हुये उज्जैन शहर को जावरा स्थित एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज से जोड़ने के लिये यह निर्णय लिया गया है । इसी एक्सप्रेस मार्ग को उज्जैन से जोड़ने के लिए उज्जैन गरोठ फोर लेन भी बन रहा है.

देश में सीएए लागू

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने सीएए को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इसको लेकर बड़ा ऐलान हो गया। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने सीएए के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। सीएए नियम जारी किये जाने के बाद, बगैर दस्तावेज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों को नागरिकता मिलेगी। इसके लिए इन लोगों को केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होगा।

गौरतलब है कि साल 2019 में केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता का प्रस्ताव दिया गया था। इसके नियमों के मुताबिक नागरिकता से जुड़े अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होंगे। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अब तक अधिसूचित किया जाना बाकी था, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है।

संसदीय कार्य नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की मंजूरी के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए अन्यथा सरकार को लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समितियों से अवधि में विस्तार करने की मांग करनी होगी। 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समिति से नियमित अंतराल पर अवधि में विस्तार प्राप्त करता रहा है।

गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था।

एक अधिकारी ने कहा, आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। 27 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए को लागू होने से को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का कानून है। इस बीच, पिछले दो वर्षों में नौ राज्यों के 30 से अधिक जिला अधिकारियों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम-1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई हैं।

गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, एक अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इन तीन देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1,414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई। वे नौ राज्य जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है उनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं। असम और पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है, लेकिन सरकार ने इन दोनों राज्यों में से किसी भी जिले को अब तक नागरिकता प्रदान करने की शक्ति नहीं प्रदान की है।

महाभारत से कम नहीं है लोकसभा चुनाव-नकवी

बेहरामपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को यहां कहा कि 2024 का चुनाव कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत से कम नहीं है, जहां सत्य से असत्य और धर्म से अधर्म का मुकाबला है।

स्वतंत्र, निष्पक्ष, भय और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करें पर्यवेक्षक-मुख्य चुनाव आयुक्त

नई दिल्ली। पर्यवेक्षकों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका याद दिलाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उन्हें स्वतंत्र, निष्पक्ष, भय और प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

चुनाव आयोग ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आगामी आम चुनावों से पहले राज्यों में तैनात किए जाने वाले पर्यवेक्षकों के लिए एक ब्रीफिंग का आयोजन किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हाइब्रिड मोड में आयोजित ब्रीफिंग बैठक में आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय राजस्व सेवा और कुछ अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों के 2150 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सीईसी ने इस बात पर जोर दिया कि आयोग के प्रतिनिधियों के रूप में पर्यवेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे खुद को पेशेवर रूप से संचालित करें और उम्मीदवारों सहित सभी हितधारकों के लिए सुलभ हों। उन्होंने उनसे मतदान केंद्रों का दौरा करने और भूगोल से परिचित होने और किसी भी कमजोरियों और संवेदनशील क्षेत्रों का जायजा लेने को कहा।

ईसीआई ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आगामी आम चुनावों के लिए सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों को जानकारी देने के लिए दिन भर का सत्र आयोजित किया।

सिंहस्थ के मद्देनजर उज्जैन में नया शासकीय मेडिकल कॉलेज बनेगा-मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। सिंहस्थ के दृष्टिगत उज्जैन में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु केवल सिविल कार्यों के लिये 592.30 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रि-परिषद ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिये रबी विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ पर 125 रूपये प्रति क्विंटल बोनस भुगतान की भी स्वीकृति प्रदान की। इस पर 3850 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आएगा। विभागाध्यक्ष कार्यालय संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व एवं संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सतपुड़ा भवन को वर्तमान में पदस्थ अमले सहित उज्जैन स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में समर्थन मूल्य विकेन्द्रीकृत योजना के अंतर्गत खाद्यान्न के उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन एवं डेफिसिट पूर्ति के लिये आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (एक वर्ष) तक की अवधि के लिये 29 हजार 400 करोड़ रूपये की निशुल्क शासकीय प्रत्याभूति (गारंटी) की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद की बैठक में उज्जैन में सिंहस्थ 2028 आयोजन के दृष्टिगत स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिये सिविल कार्यों के लिये 592.30 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। इसके लिये आवश्यक उपकरणों एवं मानव संसाधनों की स्वीकृति बाद में दी जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण से आस-पास के जिलों की जनता को भी उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश के लोकायुक्त के पद पर न्यायमूर्ति श्री सतेन्द्र कुमार सिंह की नियुक्ति का अनुसमर्थन किया। सायबर तहसील की क्षेत्रीय आधिकारिता प्रदेश के सभी जिलों में विस्तारित करने का अनुसमर्थन करते हुए स्वीकृति दी गई। एनडीबी योजना में भोपाल के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर मार्ग (कोलार मार्ग 15.1 किमी) के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिये 305.08 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

राज्य में यूरिया, डीएपी, कॉम्प्लेक्स एवं पोटाश उर्वरकों की वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक की अग्रिम भंडारण योजना स्वीकृत की गई। इससे प्रदेश के किसानो को रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को इसके लिये नोडल एजेंसी बनाया गया है। वर्ष 2024-25 में मार्कफेड को 850 करोड़ रूपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति स्वीकृत की गई। मंत्रि-परिषद ने

नीमच, मंदसौर, श्योपुर एवं सिंगरौली के नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन एवं उपकरण क्रय के लिये 1167.95 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। नीमच के लिये 287.45 करोड़ श्योपुर के लिये 288.5 करोड़, सिंगरौली के लिये 289.74 करोड़ एवं मंदसौर के लिये 302.26 करोड़ रूपये की स्वीकृती दी गई है।

केन्द्र प्रवर्तित योजना में मेडिकल कॉलेजों के साथ नये नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिये मंत्रि-परिषद ने 192.40 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश के 13 जिलों दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सतना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, श्योपुर एवं सिंगरौली में नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज के लिये 14.80 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। इससे इन जिलों एवं आस-पास के सभी नागरिको को चिकित्सा सुविधा का लाभ एवं छात्र-छात्राओं को सुगमतापूर्वक नर्सिंग संवर्ग की शिक्षा मिल सकेगी।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में निःशुल्क शव वाहन संचालन की स्वीकृति प्रदान की है। शासकीय अस्पतालों में उपचार के दौरान संस्थागत मृत्यु, सड़क दुर्घटना/आपदा में मृत्यु पर मृतक की पार्थिव देह को ससम्मान निःशुल्क शव वाहन से गंतव्य स्थल तक पहुँचाया जायेगा। शव वाहन संचालन का दायित्व लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास होगा। अभी यह दायित्व नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पास है।

श्री महाकालेश्वर भगवान के पंच मुखारबिंद को लगाया 125 किलोग्राम काजू का भोग

उज्जैन। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया सोमवार 11 मार्च को भगवान श्री महाकालेश्वर ने पंच मुखारविंद में दर्शन दिये। भगवान महाकाल के पंच मुखरविंद में एक साथ श्री छबिना, श्री मनमहेश, होल्कर, उमामहेश, श्री शिवतांडव स्वरूप को पुणे के डॉ. सागर, डॉ. साधना, पुत्र साराध्य, पुत्री साध्या कोलते परिवार द्वारा 125 किलोग्राम काजू का भोग अर्पित किया गया।

संध्या आरती में अर्पित किये भोग में सभी तरह के ड्रायफ्रूट में सोने एवं चांदी का वर्क लगाकर अर्पित किये गये।

प्रतिनिधि मुरली मनोहरजोशी ने बताया कि महाशिवरात्रि महापर्व पर विश्वप्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्री महाकालेश्वर भगवान के अनन्य भक्त पुणे के डॉ. सागर, डॉ. साधना, पुत्र साराध्य, पुत्री साध्या कोलते परिवार द्वारा शिव नवरात्रि दरम्यान 9 दिनों तक महाराज भोग का चढ़ावा और राजघराना उट्टन अर्पित किया गया लगभग 24 लाख राशि का महाराजभोग और 11 लाख राजघराणा उट्टन करीब 35 लाख का भोग श्री महाकालजी के शिव नवरात्रि के 9 दिन तक तथा महाशिवरात्रि के प्रमुख दिन महाराज भोग तथा राजघराना उट्टन अर्पित किया गया। फाल्गुन कृष्ण पंचमी से प्रारंभ हुए महाशिवरात्रि महापर्व के प्रथम दिन महाराजभोग में बाबा महाकाल को 125 किलोग्राम खजूर, 1 मार्च को 125 किलोग्राम अक्रोड, 2 मार्च को 125 किलोग्राम जरदालु का भोग, 3 मार्च को 125 किलोग्राम पुरंदरी अंजीर का भोग, पांचवें दिन 125 किलोग्राम खिश्मिश का भोग, छठे दिन 125 किलोग्राम सांगली का काला बेदाणा का भोग, सातवें दिन डब्ल्यू 180 125 किलोग्राम काजू का भोग, आठवें दिन 125 किलोग्राम पिश्ते का भोग, नवे दिन 125 किलोग्राम बादाम का भोग अर्पित किया गया। चांदी के थाल में उट्टन के साथ 25 किलो हल्दी भी बाबा को दूल्हा स्वरूप में लगाने हेतु अर्पित की गई। चांदी के थाल में प्रतिदिन 9 दिनों तक सुबह अलग भोग लगाया गया। महाशिवरात्रि के 10 दिन के त्यौहार में 11 लाख राशि का राजघराना उट्टन हिरक, स्वर्ण, रजत, पुष्कराज, आदि नौ रत्न का भस्म, चंदन तथा दुर्लभ दिव्य वनस्पति से मिश्रित राजघराना उट्टन रजत पात्र में चढ़ाया गया तथा स्वर्ण वर्ख जड़ित काजू, बादाम, पिस्ता, अंजीर, जरदालू, खजूर, अकरोड, खिश्मिश, काला बेदाणा का भोग चांदी के थाल में अर्पित किया गया।

पुणे के डॉ. सागर, डॉ. साधना, पुत्र साराध्य, पुत्री साध्या कोलते ने बताया कि बाबा महाकाल की कृपा से चारों कंपनी साराध्यन हेल्थकेयर प्रायवेट लिमिटेड, साध्यसार हेल्थकेयर प्रायवेट लिमिटेड, नई कंपनी सॅटर्न 7 कॉस्मोहिल प्रायवेट लिमिटेड, सोलस्टीक 22 के कॉस्मोहिल ओपीसी प्रायवेट लिमिटेड प्रगति पर है। सभी का कल्याण हो और आगे भी चारों कंपनी तरक्की तथा और नई उंचाईयां छूने पर श्री बाबा महाकालजी की कृपा निरंतर बनी रहे, कंपनी से जुड़े सभी लोगों के साथ सभी सुखी रहे इसी मनोकामना के साथ बाबा महाकाल से प्रार्थना की।

डॉ. सागर, डॉ. साधना, पुत्र साराध्य, पुत्री साध्या इनके परिवार सदस्य पूर्णतः उन्नति हेतु यह महाराजभोग तथा राजघराना उट्टन कंपनी के प्रतिनिधि मुरली मनोहरजोशी ने पूर्ण कार्यान्वित किया गया।

पुलिस पेंशनर्स कर्मचारी ने पेंशन में 8 प्रति. की बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया

उज्जैन। कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक संकुल भवन पर पुलिस पेंशनर्स कर्मचारी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सोपा गया। जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दो बार चार-चार परसेंट कर के महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। लेकिन जो उन्हें पेंशन मिल रही है उस में अभी तक एड नहीं किया गया है। कर्मचारियों को जो पेंशन मिल रही है वह पुराने नियम से ही मिल रही हैं। जो कि चार-चार परसेंट दो बार की बड़ा कर आठ परसेंट पेंशन में बड़ा कर मिलनी चाहिए थी जोकि नही बड़ाई गई हैं। इसी के चलते सभी पेंशनर्स कर्मचारियों ने कोठी पर एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सोपा और कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों ने कहां की अगर जल्द ही हमारी पेंशन में 8त्न की बढ़ोतरी नहीं की गई तो आने वाले लोकसभा चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे।

पेंशनर्स को केन्द्र के बराबर महगाई राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति लेना पड़ती है और छत्तीसगढ़ सरकार को म.प्र. सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है।

इस कारण पेंशनर्स को समय पर महंगाई राहत नहीं मिल पाती है और एक साल बाद महंगाई राहत के आदेश होते हैं, जिससे पेंशनर्स को लाखों रूपयों का नुकसान उठाना पड़ता है।

पूर्व सरकारों से भी कई बार पेंशनर्स संगठनों द्वारा धरना आदोंलन ज्ञापन आदि इस संबंध में दी जा चुके है। परंतु कोई निराकरण नहीं हो पाया है। अब जब म.प्र. व छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें है दोनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसी समनवय से उपरोक्त बंधनकारी धारा को समाप्त करने के लिए अपनी अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजकर उपरोक्त धारा को समाप्त कराने की कृपा करे ताकि दोनो राज्यों के पेशनर्स को इस ज्वलंत समस्या से निजात मिल सके और बुजुर्ग पेंशनर्स को समय पर कर्मचारियों के साथ महगाई राहत प्राप्त हो सके। ज्ञापन देने के समय पुलिस पेंशनर्स कर्मचारी के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

तीन मातृशक्ति सम्मानित हुई

उज्जैन। श्रीधाम आश्रम नील गंगा पर शिवार्चन काव्य संध्या के आयोजन में समाज में विभिन्न प्रकल्पों के द्वारा महिलाओं के द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को रेखांकित करते हुए विचार क्रांति साहित्य मंच द्वारा संजीवन शक्ति सम्मान हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ अनुराधा दुबे को, स्वयंप्रभा अनुराधा नागर भगवताचार्य को सामाजिक गतिविधियों के लिए भक्ति सम्मान एवं साहित्य के प्रति समर्पण भाव रखने वाली (दृष्टि बाधित दिव्यांग) कवयित्री श्रीमती कोमल वाधवानी को अनुरक्ति सम्मान समिति के अध्यक्ष सुगनचंद जी जैन एवं संरक्षक माया मालवेंद्र बधेका के द्वारा प्रदान किए गए।

जानकारी देते हुए सदस्य दिलीप जोशी ने बताया कि इस अवसर पर श्रीधाम के संचालक अमिताभ त्रिपाठी एवं आश्रम के महंत श्याम दास जी ने ट्रस्ट परिवार तथा विचार क्रांति मंच द्वारा सभी मातृ-शक्तियों सहित कवि अशोक भाटी एवं शोभा छानीवाल को सम्मानित किया। इस अवसर पर नन्ही बालिका आयुशी विश्वकर्मा ने शिव भजन पर नृत्य कर कार्यक्रम में समा बांधा।काव्य संध्या में डाक्टर राजेश रावल ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की वहीं शहर के वरिष्ठ कवि कमलेश व्यास मानसिंह शरद प्रो रवि नगाइच राजेंद्र जैन सत्यनारायण नाटाणी सत्येन्द्र अक्षय चवरे अनुज पांचाल अर्जन सिंह पंवार सुनीता राठौर पुष्पा चौरसिया श्वेतिमा निगम शीला तोमर शोभा शर्मा अदिति शर्मा डॉ खुश्बू बाफना आशा गंगा शिरोढोनकर आयुशी धाड़ीवाल श्रुति श्री जी आभा व्यास जय व्यास ओम प्रकाश कुमायु आदि रचनाकारों ने रचना पाठ कर अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। संयोजक अनिल पांचाल सेवक ने उपरोक्त कार्यक्रम का सफल संचालन किया माया मालवेंद्र बधेका ने आभार व्यक्त किया। जानकारी कमल पटेल ने दी।

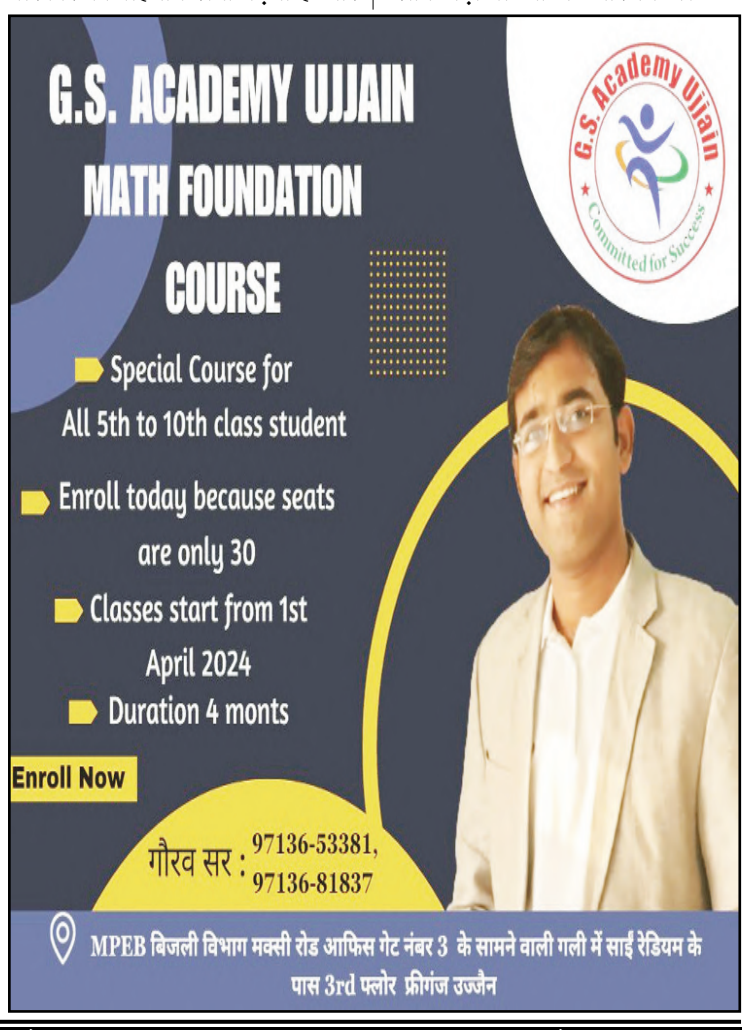

स्वताधिकारी/प्रकाशक मनमोहन शर्मा के लिये साप्ताहिक उज्जैन टाइम्स 110, तिरुपति एवेन्यू, होटल नत्रक्ष के पीछे, पंचक्रोशी मार्ग, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं ज्योति ट्रेडर्स एवं प्रिन्टर्स न्यू रोड़, उज्जैन से मुद्रित।
● प्रधान सम्पादक : मनमोहन शर्मा मोबा. 9827233734 manmohan680@gmail.com (सभी वाद-विवादों का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)। (म.प्र. शासन से 01-04-1997 से समाचार पत्र विज्ञापनों हेतु अनुमोदित)